

प्रेषक,

राधा रत्नाली,
राधिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

१. प्रमुख सचिव,
गृह/कार्मिक/वन
उत्तराखण्ड शासन।

२. सम्रत विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(व०आ०-सा०नि०)अ-न०-७

देहरादून दिनांक २६ मई २००९

विषय—अखिल भारतीय सेवा/उत्तराखण्ड राज्य के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों तथा प्रतिनियुक्त पर कार्यरत कार्मिकों को वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप ऐरियर के भुगतान के विषय में रप्तीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक छठवें केन्द्रीय गेतन आयोग की संस्थानियों के कम में केन्द्र सरकार के हारा दिनांक १-१-२००६ से वेतनमान पुनरीक्षण हेतु भारत सरकार के हारा निर्गत अधिसूचना संख्या-४७० दिनांक २९ अगस्त, २००८ के कम में उत्तराखण्ड राज्य के कर्मचारियों के लिये उक्त तिथि से वेतनमान पुनरीक्षण हेतु गठित छठवीं गेतन समिति की संस्थानि के कम में दिनांक १-१-२००६ से वेतनमान पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या-३९५/XXVII(7)/२००८ दिनांक २७ अक्टूबर, २००८, शासनादेश संख्या-२७/XXVII(7)(स्प०-१)/२००९ दिनांक १३ फरवरी २००९ के प्रततर-७ में वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का ४० प्रतिशत वित्तीय वर्ष २००८-२००९ में ३० भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है एवं शासनादेश संख्या-२०५/XXVII(1)/२००९ दिनांक २५ नावं २००९ के हारा वर्ष २००९-१० का भुगतान जुलाई, २००९ के बाद किये जाने के प्राविधानों में संशोधन करते हुए यह कहने का निचेश हुआ है कि—

२— अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में ये अधिकारी जो दैक से भुगतान प्राप्त करेंगे उन्हें ४० प्रतिशत वर्ष २००८-२००९ में तथा ३० प्रतिशत वर्ष २००९-२०१० में ऐरियर का भुगतान प्राप्त होगा, परन्तु जो अधिकारी राज्य के कोणागारी से भुगतान प्राप्त करेंगे उन्हें वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक १३ फरवरी, २००९ के अन्वयन संभवतः जुलाई माह २००९ के पूर्व भुगतान नहीं हो पायेगा, साथ ही ३० प्रतिशत वर्ष २००९-१० में तथा ३० प्रतिशत वर्ष २०१०-११ में भुगतान होगा, जिससे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में दो मानक हो जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त दिनांक १-४-२००८ भारत सरकार के हारा की जायेगी। अतः यर्णित स्थिति में अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्ति हो गये अधिकारियों को पेशन के अवशेष का भुगतान वित्तीय वर्ष २००९-२०१० के आय व्यवक्त में प्राविधानित घनराशि से किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3— उत्तराखण्ड राज्य के जिन कार्मिकों की सेवा निवृत्ति के 6 माह या इससे कम शेष हैं और उनके जी०पी०ए४० की कटीतियां बन्द किये जाने की प्रक्रिया उत्तराखण्ड भविष्य निधि नियमावली २००६ के अनुसार प्रबलन में है अतः ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में देय सभी अवशेष की धनराशि का भुगतान भी नकद किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि कोई कार्मिक उक्त अवशेष से अपने भवन निर्माण अग्रिम/कार अग्रिम की शेष वस्त्र विस्त /मूलधन/ब्याज का समायोजन करना आवश्यक समझता है तो वह ऐसी कटीतियां एवं आग्रकर की कटीती अवशेष धनराशि से करा सकता है अन्यथा नकद भुगतान किया जाय।

4— ऐसे कार्मिक जो राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे अथवा प्रभाजन के फलस्वरूप ये उत्तराखण्ड राज्य से उत्तरार्देश राज्य के लिये कार्यभुक्त हो गये हों ऐसे प्रकरणों में दो भागों में भुगतान करने के रथान पर समर्त अवशेष की धनराशि इस आदेश के प्रस्तर-२ व ३ की भाँति वित्तीय वर्ष २००९-१० के बजट प्रादिधानों के राष्ट्रेक्ष यदि अब भी उत्तराखण्ड में उनके भविष्य निधि खाते हों तब उसमें स्थानान्तरण अथवा नकद भुगतान किया जाय।

उक्तानुसार की जा रही व्यवस्था के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक १२ अक्टूबर २००८, दिनांक १३ फरवरी २००९ शासनादेश संख्या-२५/xxvii(7)प्रति०/२००९ दिनांक १३ फरवरी २००९ एवं शासनादेश संख्या- २०५/xxvii(१)/२००९ दिनांक २५ मार्च २००९ के संगत प्रस्तर फैबल उक्त रीमा तक ही संशोधित समझे जाय।

भवदीया,

(स्वास्थ्य रत्न)

संविद्, वित्त।

संख्या: १५० (१)/xxvii(७)/२००९ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित:-

१. भाग्यलेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. संविद्, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
३. संविद्, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
४. संविद्, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
५. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
६. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
७. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
८. निदेशक, कौशागार एवं वित्त सेवायें सह रेटेट इन्टर्नल आौडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
९. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
१०. उत्तराखण्ड संधिवालय के समर्त अनुभाग।
११. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
१२. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
१३. गाड़े फाइल।

आज्ञा
—१५०—
(टी०एन०प०स०)
अपर संविद्।